



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA-70/2021-22/

Date 05.01.2021

To

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of revised rate of Dearness Relief to Bihar State Government Pensioners/ Family Pensioners w.e.f. 01.07.2021 (i) @31%, who are drawing pension in revised pay scale as per 7th Central Pay Commission, (ii) 189%, who are drawing pension in pre-revised pay scale as per 6th Central Pay Commission, and (iii) 356%, who are drawing pension in pre-revised pay scale as per 5th Central Pay Commission And Grant of 28% Dearness Relief w.e.f. 01.07.2021 admissible to the pensioners/ family pensioners of Patna High Court, Patna who are getting pension in revised pay structure – reg.

Ref: 1. Resolution No. 3A-2-PR-(Allowance)-08/2013/7530/Fin dated 09.11.2021 of Government of Bihar, Department of Finance
2. Resolution No. 3A-2-PR-(Allowance)-08/2013/6600/Fin dated 27.09.2021 of Government of Bihar, Department of Finance
3. Memo No. 37407-11/Accounts dated Patna 31.08.2021 of Registrar (Establishment) I/c, High court of Judicature at Patna
4. SSA No. Pen-9-SSA-006 dated 25.11.2021 received from the Office of the Accountant General (A&E), Bihar, Patna.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Office of the Accountant General (A&E), Bihar, Patna regarding grant of revised rate of Dearness Relief to Bihar State Government Pensioners/ Family Pensioners w.e.f. 01.07.2021. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link “Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners”. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

2. The Office of the Accountant General (A&E)
Bihar, Patna (for information)


Sr. Accounts Officer

दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812



फैक्स /Fax - 0612-2221056
तार /Gram : ACCOUNTS
टेली /Tele

प्र० महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार,
पटना

OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No.
संख्या :-
Date:
दिनांक:-

Pen-9 - 1006

25/11/2021

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrh	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E), Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrh, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.- 2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No. 6599, 6600 dt. 27-09-2021, Registrar

(Est.) S/c High Court Patna - memo No. 37407-11
7530 dt. 09-11-2021 dt. 31-08-2021.

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully

Suman
[Signature]

Sr. Accounts Officer

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:...../2021

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक-20/07/2021 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5422, दिनांक-19/08/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/4/2021-E-II(B) दिनांक-25/10/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।
- (iii) महँगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई राहत दिनांक-01/07/2021 से भुगतान है और बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान माह नवम्बर, 2021 के पेंशन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 से आकलित बकाये राशि का भुगतान इसके पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।



ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7530/वि०

पटना, दिनांक:-09.11.2021

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:-

षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-8952/वि०, दिनांक-11.11.2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक-01.07.2019 के प्रभाव से 164 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/3/2008-E-II(B) दिनांक-13.08.2021 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि:-

- (i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 164 प्रतिशत के स्थान पर 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी जाती है।
- (ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।
- (iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

CK
1h
08/01/21

5. उक्त बड़ी हुई दर से महँगाई राहत दिनांक-01/07/2021 से भुगतये है और बड़ी हुई दर से महँगाई भत्ता का भुगतान माह नवम्बर, 2021 के पेंशन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 से आकलित बकाये राशि का भुगतान इसके पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त महँगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

H0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक:-09.11.2021

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-7530/वि०

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

Agren-627 (21-22)

पत्रांक-3ए-2-वे०पु०-(भ०)-08/2013-

/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-8951, दिनांक-11.11.2019 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01.07.2019 के प्रभाव से 312 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1/3/2008-E-II(B), दिनांक-13.08.2021 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/भत्ते प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 312 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 356 प्रतिशत की स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

- (i) पंचम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।
- (ii) दिनांक 01.01.2006 के पूर्व एवं दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया जाय।

- (iii) महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायेगा, किन्तु विवेकानंद वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- (iv) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपसे में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अप्रनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भ०)-08/2013-.....6600/वि० पटना, दिनांक:-27-09-2021

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(GEM)
2

05/09/2021

A.G.B.
29 SEP 2021
PATNA

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

27/9/2021

300021H0172

Per 09
4/10

Not to be Addressed to Registrar by
Name

CE-07 7- No - 49

(P.H.C. Sch. 1-7 A)

No.

/Accounts

Pen-106
15/8

Anamika T.

Registrar (Establishment) I/c

HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Fax No. : 0612-2504088

Ph. Office : 0612-7158651

Dated Patna the /08/2021

To

The Secretary (Resources),
Finance Department,
Govt. of Bihar, Patna.

Sub- Sanction of 28% Dearness Relief in place of 17% w.e.f. 01.07.2021 admissible to the Pensioners/Family Pensioners of the State Govt. getting pension in revised pay structure.

Sir,

With reference to para-8 of the Resolution issued under Memo no. 5422/F dated 19.08.2021 on the subject noted above, I am directed to inform you that Hon'ble the Chief Justice has been pleased to accord concurrence to the decisions of the State Govt. as contained in the aforesaid resolution for its implementation in respect of the Pensioners/Family Pensioners of Patna High Court, Patna who are getting pension in revised pay structure.

This is for your information and necessary action.

Yours faithfully,

Sd/- Anamika T.

Registrar (Establishment) I/c

Memo No. 37407-11 /Accounts, Dated, Patna the 31/08/2021

Copy forwarded to the Accountant General (A & E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna/Senior Accounts Officer (GM-9), Office of the Accountant General (A & E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna/Treasury Officer, Patna Secretariat Treasury, Sinchai Bhawan, Patna/Section Officer, I/c Accounts (General) Department, High Court, Patna & D.A. I/c Pension Table, AD (Establishment), Patna High Court, Patna (with a copy of Resolution bearing memo no. 5422/F dated 19.08.2021) for information and necessary action.

Registrar (Establishment) I/c

GE-07
H.E.P.
related
to NF-05
10/08/21
092140591
2092100000
21-01

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF FINANCE

RESOLUTION

Patna, dated /2021

Sub :- Sanction of 31% dearness relief in the place of 28%, w.e.f. 01.07.2021 to the pensioners/family pensioners of State Government receiving pension in revised pay structure – reg.

In the light of Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, OM No. 1/1/2020-E-II(B) dated 20.07.2021, sanction had been accorded for dearness relief at the rate of 28% w.e.f. 01.07.2021 to the pensioners/family pensioners of the State Government, receiving pension in revised pay structure, vide Department of Finance, Resolution No. 5422, dated 19.08.2021.

2. Vide Government of India, Ministry of Finance, OM No. 1/4/2021-E-II(B) dated 25.10.2021, sanction has been accorded to increase the rate of dearness allowance from 28% to 31% w.e.f. 01.07.2021 to Central Government employees drawing pay in revised pay structure.

3. The State Government also accord sanction of dearness allowance/relief to their employees/ pensioners/family pensioners at the same rate and from the same date similar to Central Government.

4. **In the light of the above, after due consideration the following decisions have been taken by the State Government -**

- i. Sanction is accorded for 31% of dearness relief in the place of 28%, w.e.f. 01.07.2021, to state pensioners/family pensioners receiving pension in revised pay structure.
- ii. In respect of pensioners/family pensioners, payment of dearness relief shall be calculated on the basis of basic pension.
- iii. In the calculation of dearness relief, 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee and the amount less than 50 paise shall be ignored.
- iv. Payment of the amount of above dearness relief shall be made in cash.

5. The above increased rate of dearness relief is payable w.e.f. 01.07.2021 and the payment of dearness allowance at increased rate shall be made with the pension for the month of **November, 2021**, but payment of the arrear amount calculated from the previous month of **July, 2021** shall be made thereafter.

6. Payment of dearness allowance on pension is admissible to those pensioners also, including re-employed pensioners, who are receiving compensatory pension, old age pension, superannuation and disability pension. The relief shall also be payable to those receiving provisional pension/family pension and extraordinary pension.

7. In order to avoid delay in the payment of dearness relief to pensioners, orders are issued under Rule 206 of Bihar Treasury Code, 2011 for the payment of relief without the authorization of the Accountant General, Bihar in the case of pensioners receiving pension within the state. The Treasury Officers are also directed to circulate the copies of this order to all authorized Public Sector Banks for making immediate payment to the pensioners receiving payment through

banks. Release of dearness relief outside Bihar State shall be made only on the authorization letter of the Accountant General, Bihar. The Accountant General, Bihar is requested that the Accountants General concerned with the pensioners receiving pension outside Bihar State shall be authorized urgently for the payment of relief on pension under intimation to the Department of Finance.

8. Payment of above dearness relief on the pension of the pensioners of High Court/Bihar Legislative Assembly/Bihar Legislative Council shall be made with the sanction of the Chief Justice, High Court, Patna/Speaker, Bihar Legislative Assembly/Chairman, Bihar Legislative Council.

ORDER : Ordered that this Resolution be published in the next edition of the Gazette of Bihar, for the information of General Public.

/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources)
Department of Finance

Endt No. 3A-2-Ve.Pu.-(Bha.)-08/2013-7530/Vi.

Patna, dated 09.11.2021

Copy to :- The Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, Patna, for information and necessary action.

Sd/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources)
Department of Finance

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF FINANCE
RESOLUTION

Patna, Dated

Sub :- Sanction of 189% dearness allowance/relief in the place of 164% w.e.f. 01.07.2021 to State Government Employees/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in unrevised pay scales as per the Sixth Central Pay Commission.

1. Vide Department of Finance, Resolution No.8952/Vi. dated 11.11.2019, sanction had been accorded for dearness allowance/relief at the rate of 164% w.e.f. 01.07.2019 to State Government Employees//Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in unrevised pay scale as per the Sixth Central Pay Commission, similar to Central Government.

2. Vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, OM No.1/3/2008-E-II(B) dated 13.08.2021, sanction has been accorded to increase the rate of dearness allowance of 164% to 189% w.e.f. 01.07.2021, to Central Government employees drawing pay/pension in the Sixth Central Pay Scale.

3. The State Government also accord sanction of dearness allowance/relief to their employees/pensioners/family pensioners at the same rate and from the same date similar to Central Government.

4. **Hence, after due consideration decision is taken that—**

i) Sanction is accorded for 189% dearness allowance in the place of 164% w.e.f. 01.07.2021, to State Government Employees/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in unrevised pay scales as per Sixth Central Pay Commission.

ii) Dearness allowance will be calculated on the basis of the sum of Pay Band and Grade Pay received in unrevised pay scale and it will not include Special Pay and Personal Pay.

iii) In respect of Pensioners/Family Pensioners, payment of dearness relief will be calculated on the basis of basic pension.

iv) In the calculation of dearness allowance/ relief 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee and the amount less than 50 paise shall be ignored.

5. The above increased rate of dearness relief is payable w.e.f. 01.07.2021 and the payment of dearness allowance at increased rate shall be made with the pension for the month of **November, 2021**, but payment of the arrear amount calculated from the previous month of **July, 2021** shall be made thereafter.

6. Payment of dearness allowance on pension is admissible to those pensioners also, including re-employed pensioners, who are receiving compensatory pension, old age pension, retirement and disability pension. The relief shall also be payable to those receiving provisional pension/family pension and extraordinary pension.

7. In order to avoid delay in the payment of dearness relief to pensioners, orders are issued under Rule 206 of Bihar Treasury Code, 2011 for payment of relief without the authorization of the Accountant General, Bihar in the case of pensioners receiving pension within the state. The Treasury/Sub Treasury Officers are also directed to circulate the copies of this order to all authorised Public Sector Banks for making immediate payment to the pensioners receiving payment through banks. Release of dearness relief outside Bihar State shall be made only on the authorisation letter of the Accountant General, Bihar. The Accountant General, Bihar is requested that the Accountants General concerned with the pensioners receiving pension outside Bihar State shall be authorized urgently for the payment of relief on pension under intimation to the Department of Finance.

8. Payment of above dearness relief in the pension of the pensioners of High Court/ Bihar Legislative Assembly/ Bihar Legislative Council shall be made with the sanction of the Chief Justice, High Court, Patna/ Chairman, Bihar Legislative Assembly/Speaker, Bihar Legislative Council.

ORDER : Ordered that this Resolution be published in the next edition of the Gazette of Bihar for the information of general public.

/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources)
Department of Finance

Endt No. 3A-2-Ve.Pu.-(Bha.)-08/2013-7530/Vi.

Patna, dated 09.11.2021

Copy to :- The Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, Patna, for information and necessary action.

Sd/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources)
Department of Finance

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF FINANCE
RESOLUTION

Patna, Dated

Sub :- Sanction of 356% dearness allowance/relief in the place of 312%, w.e.f. 01.07.2021 to State Government Employees/Pensioners/Family Pensioners receiving pay / pension in unrevised pay scales as per Fifth Central Pay Commission.

Vide Department of Finance, Resolution No.8951 dated 11.11.2019, sanction had been accorded for dearness allowance/relief at the rate of 312% w.e.f. 01.07.2019 to State Government employees receiving unrevised pay/pension as per the Fifth Central Pay Commission.

2. Vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, OM No.1/3(2)/2008-E-II(B) dated 13.08.2021, sanction has been accorded to revise the previously sanctioned rate of 312% of dearness allowance/relief to 356% w.e.f. 01.07.2021, to Central Government employees receiving un-revised pay/allowance as per the Fifth Central Pay Commission (i.e. whose pay revision has not been done from 01.01.2006).

3. The State Government also accord sanction of dearness allowance/relief to their employees/ pensioners/family pensioners at the same rate and from the same date similar to Central Government.

4. **Hence, after due consideration decision is taken that—**

- (i) Sanction is accorded for 356% dearness allowance/relief in the place of 312%, w.e.f.01.07.2021, to State Government Employees/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in unrevised pay scales as per Fifth Central Pay Commission.
- (ii) Rate of dearness allowance/relief to those employees receiving pay in the revised pay scale (not revised at present) applicable w.e.f. 01.01.1996 and prior to 01.01.2006 and who have been given the benefit of dearness allowance equivalent to the amount of 50 percent of basic pay as dearness pay w.e.f. 01.01.2005, may be increased from 312% to 356%, w.e.f. 01.07.2021.
- (iii) Payment for dearness allowance/relief will be calculated on the basis of the combined sum of basic pay/pension and dearness pay/ pension, but dearness allowance shall not be permissible on Special Pay/Personal Pay.
- (iv) In the calculation of dearness allowance/relief, 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee and the amount less than 50 paise shall be ignored.
- (v) Payment of the amount of above dearness allowance/ relief shall be made in cash.

213
20/11/19

The Treasury Officer shall immediately make the due payment provisionally, without waiting for authorization letter of the Accountant General/Finance Personal Claims Fixation Cell.

5. Payment of above dearness allowance/relief in unrevised pay scale to the employees/pensioners/family pensioners of High Court, Patna/Bihar Legislative Assembly/Bihar Legislative Council shall be made with the sanction of the Chief Justice, High Court, Patna/Speaker, Bihar Legislative Assembly/Chairman, Bihar Legislative Council.

ORDER : Ordered that this Resolution be published in the next edition of the Gazette of Bihar for the information of general public.

/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources)
Department of Finance

Endt No. 3A-2-Ve.Pu.-(Bha.)-08/2013-6600/Vi.

Patna, dated 27.09.2021

Copy to :- The Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, Patna, for information and necessary action.

Sd/-
(Lokesh Kumar Singh)
Secretary (Resources)
Department of Finance